प्रकाशनार्थ

पटना, 26 अगस्त। अगले पांच वर्षों में बिहार में एक करोड़ नौकरियां सृजित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने उन निवेशकों को केवल एक रुपये की दर से 10 से 25 एकड़ तक की भूमि प्रदान करने की घोषणा की है, जो राज्य के लिए कम से कम एक हजार नौकरियां सृजित करेंगे। उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि की कमी की समस्या को दूर करने हेतु सरकार की भूमि बैंक में बीते वर्ष लगभग 15 हजार एकड़ भूमि जोड़ी गई है। बिहार के माननीय उद्योग मंत्री श्री नितीश मिश्रा ने आज एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आद्री द्वारा आयोजित एक "उद्योग और नवाचार के माध्यम से बिहार का भविष्य निर्माण" नामक कार्यक्रम में मुख्य भाषण देते हुए यह घोषणा की। माननीय मंत्री ने यह भी गर्वपूर्वक बताया कि वर्तमान में राज्य में लगभग 1600 स्टार्टअप सक्रिय हैं, जिनमें से 300 का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विनिर्माण और सेवा उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि बिहार केंद्र सरकार की सोच के अनुरूप पूर्वी भारत में एक प्रमुख विकास इंजन बनने की दिशा में अग्रसर है।

इससे पहले आद्री की सदस्य सचिव डॉ. अश्मिता गुप्ता ने उद्योग विभाग को सौंपे गए एक रिपोर्ट के निष्कर्ष प्रस्तुत किए, जिसका शीर्षक था "बिहार में औद्योगिक विकास और कौशल विकास के अवसर।" रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों में यह पाया गया कि राज्य में उद्योगों का संकेंद्रण पटना, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जैसे प्रमुख शहरी क्षेत्रों में है। अतः सरकार को मधुबनी, जहानाबाद, अरवल जैसे उभरते औद्योगिक गलियारों में निवेश कर इस असंतुलन को दूर करना चाहिए। औद्योगिक रणनीति बनाते समय सरकार को रोजगार सृजन, सस्टेनब्लिटी और विकास पर ध्यान देना चाहिए। उद्योग के प्रकार का चयन करते समय इन पहलुओं का संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सरकार को प्रभावी निर्णय-निर्धारण के लिए बेहतर डेटा प्रबंधन और विज़ुअलाइज़ेशन को अपनाना चाहिए।

कार्यक्रम में यूनाइटेड किंगडम के यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग की प्रोफेसर नेहा हुई और उमा कंभरापति ने भाग लिया। आद्री की डॉ. मौसमी गुप्ता, डॉ. सुनीता लाल और डॉ. संचित महापात्रा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। धन्यवाद ज्ञापन जेएसएस-आद्री के निदेशक डॉ. संदीप कुमार ने प्रस्तुत किया।

(अभिषेक प्रसाद)